no formal agreement was signed. But areas of potential co-operations were identified.

SHRI VINODBHAI B. SHETH. In this country we have got electronics Engineers of a very high calibre and still we are lagging behind in so far as electronic applicances are concerned. I would like the hon. Minister to give specific reply as to whether the Government is thinking to introduce electronic devices in the services like ports, railways, aircrafts, etc

MR SPEAKER. It does not arise here

अनियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

+

*685. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1978 से मार्च, 1979 तक की अवधि में रुई के मूल्यों में कमी होने के बावजूद कपड़ा मिलों ने इस अवधि में अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की थी,

(ख) यदि हां, तो 1 सितम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि में रुई के थोक विक्रय मूल्य सूचकांक में कितनी कमी हुई थी और उसी अवधि में अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई थी,

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा तैयार किये जाने वाले अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों को विनियमित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य में वृद्धि पर नियंत्रण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि में कच्ची रुई का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक 2.4 प्रतिशत गिरा, जबकि उसी अवधि में सूती कपड़े के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). कपड़े के मूल्यों में घटा-बढ़ी के समूचे प्रश्न के संबंध में सूती वस्त्र उद्योगपतियों से चर्चा हुई थी तथा उद्योगपतियों से कपड़े के मूल्यों को कम करने के बारे में तुरन्त कदम उठाने के लिये कहा गया था। उद्योगपतियों ने कुछ सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल : क्रय शक्ति की कमी की वजह से अपने देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा साल के ज्यादा हिस्से में अधनंगा रहता है और सन् 64-65 के मुकाबले प्रति व्यक्ति साल की खपत में सन् 77-78 में 3 4 मीटर की कमी हुई है जो अपने में आप में बहुत एलार्मिंग है। इसके अलावा आप ने केवल छः महीने की फिगर दी है। साल भर की यह स्थिति है कि जहां पर रुई के दाम गिरे हैं साढ़े नौ परसेंट वहां कपड़े के दाम करीब तीन परसेंट बढ़ गये हैं और कपड़े के ही नहीं, सूत के, धागे के भी दाम बढ़ गये हैं। तो एक तरफ तो किसान और दूसरी तरफ जिन उद्योगों का प्राण बताना चाहते हैं, हैंडलूम वगैरह, उन को इस में नुकसान हुआ है क्योंकि धागे के दाम इतने बढ़ रहे हैं मैंन मेड फाइबर के भी और क्लाथ के भी कि उस का चलना मुश्किल हो रहा है। कल एक डेलीगेशन आप से मिला था। तो मैं यह कह रहा हूं कि जो हथकरघा, कन्ज्यूमर और किसान इन तीनों की कीमत पर मिल मालिक दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं उस के बारे में आप ने अपने जवाब में कोई जिक्र नहीं किया है कि आप की तरफ से उसके लिए क्या कार्यवाही हो रही है। आप ने खाली यह बता दिया कि मात्र मालिकों की तरफ से यह आफर है। आप ने इन दामों को रोकने के लिए क्या निश्चित कार्यवाही की यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम तो इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के लोगों से मिले और उन से हमने यह कहा कि उन लोगों ने आज जिस रूप में दाम बढ़ाए हैं वह कम किए जाने चाहिए। उसके बाद यह दाम कम करने की दृष्टि से उन की तरफ से तीन सुझाव आए हैं जिनका मैं ने यहां पर जिक्र किया। हम ने उन से बताया है कि ये तीनों सुझाव हमें मंजूर नहीं है और दामों को उन्हें गिराना पड़ेगा। सूत और कपड़ा दोनों क्षेत्रों में जहां भी दामों को बहुत बढ़ाने का सिलसिला चला है उस को गिराने का काम उन्हें करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से किसी और कदम के उठाए बिना दामों को गिराने का काम वह करेंगे। इस वक्त उन लोगों की बातचीत हमारे मंत्रालय के साथ चल रही है और अगर उन की तरफ से दाम घटने के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जो हमें मंजूर हो तो हम कोई और कदम अपनी तरफ से उठाएंगे जिस के द्वारा दामों को गिराने में मदद मिले।

श्री अनन्त राम जायसवाल : पहले कपड़े के हर मीटर पर रिटेल प्राइस छपा करती थी। आजकल वाली एक्स-फैक्ट्री प्राइस प्लस ड्यूटी छाप देते हैं और शिकायत यह है कि वह भी इतना बढ़ा कर छापते

हैं कि जिस से वे खूब फायदा उठाएं। तो क्या आप पहले की तरह रिटेल प्राइस छपाएंगी और दूसरे, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कंट्रोल लागू करेंगे ? इस के अलावा साल भर तक जो यह स्थिति रही कि बराबर कपड़े के दाम बढ़ते रहे इस बीच में आप का मंत्रालय क्यों सोता रहा इस पर कुछ प्रकाश आप डालेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दामों पर कंट्रोल लगाने का सवाल है यह जहां तक हमारी समझ है संभव नहीं है क्योंकि कपड़े के दाम पर कंट्रोल लगा कर उस को फिर अमल में लाना एक असंभव जैसी चीज हमें नजर आती है। लेकिन और कई उपाय हैं जिन को अमल में लाया जा सकता है जिन के बारे में हम इस समय विचार कर रहे हैं और जहां तक हर मीटर पर कपड़े का दाम छापने का सवाल है यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि जब दाम एक अरसे से बढ़ते रहे तो सरकार ने उस के बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री अनन्त राम जायसवाल : अरबों रुपया मिल मालिकों ने कमा लिया और खाली प्राइवेट ने ही नहीं नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने भी कमाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन इस समय 40 प्रतिशत अपना कपड़ा कंट्रोल कपड़ा बना रहा है और बाकी जो नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का कपड़ा है वह आम तौर पर चार और पांच रुपये प्रति मीटर के दाम के भीतर है, तो अरबों रुपया नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के द्वारा मुनाफे के रूप में कमाने का सवाल नहीं है। यह सही है कि निजी मिलों ने इस प्रकार की कोई अपनी नीयत नहीं दिखाई जिस से यह मालूम हो कि लोगों को कपड़ा उचित मूल्य पर मिल सके इस जिम्मेदारी को उन लोगों ने निभाया हो। तो इस पर जो कार्यवाही हमें करनी है वह कार्यवाही हम लोग करने जा रहे हैं।

श्री चिमनभाई एच शुक्ल : जहां तक इस इंडस्ट्री का सवाल है कभी भी सरकार की बात इन्होंने नहीं मानी है।

They are taking Government for granted.

तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार रा मैटीरियल और फिनिश्ड गुड्स, इन दोनों के बीच में कितना फर्क होना चाहिए यह मानती है तो सरकार जो मानती है उस के लिए वह क्या कदम उठाना चाहती है ?

एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। ये मिल वाले कभी भी मानने वाले नहीं हैं। तो क्या सरकार जिस सख्त कदम की बात करती है उस में वह यह बात भी सोचेगी कि सारी मिलों में केवल स्पिनिंग होने दे, बुनाई न होने दे ?

बुनाई का काम भारत सरकार हथकर्घा उद्योग को सौंपे। जबतक यह नहीं होगा तब तक वे अपना मुनाफा कम करने वाले नहीं हैं क्योंकि उनको मुनाफा कमाने की आदत हो गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं। इसमें मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है कि मिल मालिक इस मामले में जो रुख अपना रहे हैं वह लोकहित वाला रुख नहीं है। सामान्य लोगों की समस्याओं के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है—यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि हम सिर्फ स्पिनिंग का काम इन मिलों में करें और सारा वीविंग का काम बाहर निकाल दें—यह सम्भव नहीं होगा। जितनी पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है और जितना कपड़ा मिलें बनाती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यह चीज इस वक्त सम्भव नहीं है। रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के जो रिश्ते का सवाल है वह अलग अलग उद्योगों में अलग अलग किस्म का होता रहेगा। टेक्सटाइल मिल्स में भी रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो अन्तर है उसमें जरूर फर्क रहेगा।

श्रीमती जन्नावती : अध्यक्ष महोदय, 1966-67 में जब रूई का भाव शायद 400—500 रुपए के बीच रहा तब कपड़ा साढ़े चार, पांच रुपए मीटर पर था लेकिन आज रूई का भाव 260 पर चले जाने के बाद भी कपड़ा 11 रुपए मीटर बिक रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्या सरकार ने इस मुनाफे को कंट्रोल करके, रूई के जो उत्पादक हैं उनके साथ कोई सामंजस्य करने की चेष्टा भी की है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यही चेष्टा इस समय हो रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री जी ने अभी शायद दो तीन दिन पहले कहा कि सरकारी काटन टेक्सटाइल मिलें इस साल बहुत नफा कमायेंगी। उसका कारण यह नहीं है कि उनकी एफीशिएन्सी बढ़ गई है बल्कि उसका कारण यह है कि रूई के दाम बहुत गिर गए हैं और काटन क्लाथ के दाम बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट मिलें उनसे भी ज्यादा गडबड़ कर रही हैं। यह मंत्रालय पिछले दो साल से पेसिव स्पेक्टेटर रहा है। एक एक गज पर बीस-बीस पैसे दाम बढ़े हैं। मेरे पास काटन का इन्डेक्स है।

The cotton index for May 1977 was 214, and for October 1977 it has come down to 160.6. There is a fall of 22.6 per cent.

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप दाम कितना कम करना चाहते हैं और क्या मांग आपने रखी है ? अगर वे दाम कम नहीं करते हैं तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ? अभी जैसा यहां पर रिटेल प्राइस छापने के लिए कहा गया तो अगर पहले यह दाम छापे जा सकते थे तो अब क्यों नहीं छापे जा सकते हैं ? आप उनकी कास्टिंग करके एक्स-मिल प्राइस छापिए न कि आप उनके हाथ में दें दें कि जो भी चाहें वे छाप दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां तक एन टी सी मिल्स के मुनाफे का सवाल है, इस साल पहली बार एन टी सी. मिलों ने तीन करोड़ का मुनाफा कमाया है। मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत नहीं हो सकता कि यह मुनाफा रुई का दाम कम होने के कारण या कपड़े का दाम बढ़ाने के कारण हुआ है। जैसा मैं ने पहले बताया, एन टी.सी.की मिलें प्रति वर्ष चालीस करोड़ गज कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने के काम में लगी है जिसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है। जो दाम कपड़ा बनाने में लगता है वही दिया जाता है एन टी.सी. मिलों में मुनाफे का कारण यह है कि मार्डनाईजेशन का काम वहां पर किया गया है और एफीशिएन्सी बढ़ाने का काम भी हुआ है। मैनेजमेन्ट में जहां जहां कमजोरियां थीं उनको भी दूर करने का काम हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक कई प्रकार के प्रयास हमने डेढ़ साल में किए हैं। हमने पहली बार एन टी सी की 111 मिलों के जनरल मैनेजर्स को एक जगह पर बुलाकर, उनकी समस्याओं को समझ कर, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया ताकि उनका काम ठीक ढंग से हो। इस तरह से हम ने इस दिशा में कई प्रकार के प्रयास किए हैं जिसका नतीजा यह है कि आज एन टी सी. मुनाफे की ओर बढ़ रही है।

जहां तक मिलों द्वारा मुनाफा कमाने का सवाल है, मिलें मुनाफा जरूर कमायेंगी। कोई मिल मुनाफा कमानी है, यह कोई सवाल नहीं हो सकता है मुनाफा जरूर होगा—उद्योग में निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो—मुनाफा होगा, इस के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो उद्योग मुनाफा कमा रहे हैं और दामों पर लगाम लगाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं—इस सम्बन्ध में उन की तरफ से तीन प्रस्ताव हमारे सामने आये हैं और हम ने कहा है कि ये हमें मन्जूर नहीं है। अब जो ठोस सुझाव है वे हम ने रखे हैं और उन से जैसा जवाब आयेगा फिर उस पर कार्यवाही करेंगे।

Memorandum by Christian Welfare Association, Bihar

*687. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Christian Welfare Association presented a Memorandum to Governor of Bihar in a mass deputation on 5th March, 1979,

(b) what are their main demands;

(c) whether it is a fact that during the last one year there have been many attacks on their missions/institutions/individuals in various parts of Bihar; and

(d) the forces/institutions behind this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d) The information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House. But just a few hours back we got information from the Bihar Government and on the basis of that I wish to correct my answer.

In regard to part (a), whether it is a fact that Christian Welfare Association presented a memorandum to the Governor of Bihar, the answer is: yes, on the 5th March a memorandum was submitted to the Deputy Secretary to the Governer.

With regard to (b), the demands are: to institute a high level enquiry into the matter of the incident and find out whether there is any institutionalised agency behind this and to bring the culprits to book.

As regards the other parts of the question, information is being collected from the Government of Bihar.

श्री किशोर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं—इन के मेमोरेण्डम देने से पहले वहां कितने क्रिश्चियन-मिशनरीज के मर्डर हुए, जिस से उन के अन्दर सेन्स-आफ-इनसिक्योरिटी पैदा हुई तथा जिन मिशनरीज का मर्डर हुआ क्या उन के बारे में कोई इन्वेस्टीगेशन हुआ ? मैं यह भी जानना चाहता हूं—क्या कोई सेन्ट्रल एजेन्सी जैसे इंटेलीजेन्स ब्यूरो या कोई अन्य एजेन्सी इन क्रिश्चियन मिशनरीज के मर्डर की जांच में लगी हुई है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : मुकामा में एक क्रिश्चियन फादर की मृत्यु हुई थी, उस के बाद यह मेमोरेण्डम राज्यपाल महोदय को दिया गया। उस मेमोरेण्डम में उसके पहले की घटनाओं के बारे में जो बातें कही गई है—उन में कहा गया है कि मुंगेर में इस तरह की घटना हुई है, उस के बाद बरौनी में हुई, चनपुटिया, चम्पारन में हुई, रोहतास में हुई—इस तरह की कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। जहां-जहां इस तरह की घटनायें हुई, उन के सम्बन्ध में मैं ने अभी बताया है, लेकिन इन पर जो सूचना मांगी गई है, वह हम को अभी उपलब्ध